

दश मं बायोगैस के बढ़ते कदम: कृषि और पशु अपशिष्ट बना ईंधन उत्पादन का साधन

● पेट्रोल में इथेनॉल की तरह अब सरकार का बड़ा लक्ष्य सीएनजी एवं पीएनजी में बायोगैस का मिश्रण

सुरेन्द्र पंडित

नई दिल्ली/मेरठ, (पंजाब केसरी) : देश में बायोगैस ने वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपने कदम जमा लिए हैं। जिस तेजी से बायोगैस (मिथेन गैस) को लेकर भारत सरकार ने तेजी दिखाई, उसे देखकर लगता है कि नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को समय रहते हासिल कर लिया जाएगा। 2018 में, भारत सरकार ने सतत (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रान्सपोर्टेशन) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य विभिन्न बायोमास स्रोतों से कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन के लिए एक स्थायी परिस्थितिकी तंत्र बनाना है। बायोगैस को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम यह है कि सरकार ने गैस आपूर्तिकर्ताओं के लिए प्राकृतिक गैस (सीएनजी-पीएनजी) में 1 प्रतिशत बायोमीथेन/सीबीजी मिलाने का



प्रेस वार्ता करते मोहित धवन, छिट्टी डायरेक्टर पीआईबी मोनिका, विकास सिंह व अंकुर जग्गी।



शुगर मिल से निकले प्रेस मड का प्रोसेस करते एक कर्मचारी।



बायोगैस प्लांट के दौर के दौरान एचपीसीएल अधिकारी जानकारी देते हुए।

आदेश दिया है, जिसका लक्ष्य 2028 तक 5 प्रतिशत करना है। दावा किया जा रहा है कि बायोगैस उद्योग में देश में स्वरोजगार, ग्रामीण विकास और दीर्घकालिक आजीविका के लिए एक मजबूत क्षमता है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा संक्रीण में तेजी लाने से अक्षय ऊर्जा रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी।

गौरतलब है कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और देश में सतत परिवहन के लिए सस्ती वैकल्पिक ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(एचपीसीएल) द्वारा शुक्रवार को मेरठ में सीबीजी (कंप्रेस्ड बायोगैस) विषय पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में सरकार की सतत (सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ट्रान्सपोर्टेशन) योजना की उपलब्धियों और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया गया। पेट्रोल में

इथेनॉल की तरह अब सरकार का बड़ा लक्ष्य सीएनजी एवं पीएनजी में बायोगैस का मिश्रण है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देशभर में 106 सीबीजी प्लांट के जरिए अभी एक प्रतिशत बायोगैस का

मिश्रण सीएनजी में शुरू कर दिया है, जिसे अगले 2029 तक बढ़कर 5% तक पहुंचना है। 2029 तक देश में सीबीजी प्लांट की संख्या करीब 500 हो जाएगी जिससे इस 5% के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकेगा। मौजूदा समय में 82 सीबीजी प्लांट निर्माणाधीन हैं।

सतत योजना जिसे 1 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था, का उद्देश्य किसानों, उद्यमियों और निजी क्षेत्र को जोड़ते हुए सीबीजी उत्पादन को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश

इस क्षेत्र में अग्रणी है, जहां 22 संयंत्र चालू हो चुके हैं और 24 निर्माणाधीन हैं। कार्यक्रम के दौरान एचपीसीएल रिन्यूएबल एवं ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ मोहित धवन ने कहा कि सीबीजी प्लांट्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बन रहे हैं। इससे किसान, गोशालाएं और युवा उद्यमी सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि एचपीसीएल सीबीजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के साथ-साथ तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक (गैस प्रोजेक्ट) विकास सिंह बताया कि मंत्रालय ने सीबीजी को प्राथमिकता में रखा है और इसके लिए कई नीतिगत

प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार सीबीजी को सीएनजी और पीएनजी के विकल्प के रूप में मजबूत बना रही है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने देशभर में सीबीजी को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नेटवर्क से जोड़ने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गैल को इस योजना का संचालन सौंपा गया है, जिसके तहत घरेलू गैस के साथ सीबीजी की मिश्रित आपूर्ति सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू खंडों में) की जाएगी। इस मौके पर अंकुर जग्गी (निदेशक, सर्किल सीबीजी) ने कहा कि देश में भरपूर बायोमास संसाधन हैं, जिन्हें यदि इसे एकत्र कर उपयोग में लाया जाए तो

ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जैविक खाद के रूप में निकलने वाला एफओएम किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। कार्यक्रम में बताया गया कि कृषि अपशिष्ट, पशु अपशिष्ट, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू), प्रेसमड से बायोगैस का उत्पादन कर उसे सीबीजी में बदला जा रहा है। इसके कई फायदे सामने आए हैं- जैसे ग्रोनाहाउस गैसों में कमी, जैविक खाद से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कचरा प्रबंधन और विदेशी मुद्रा की बचत। यही नहीं इससे निकलने वाले जैविक खाद से जमीन की उर्वरा को भी बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

पंजाब में पराली जलाने का हल बायोगैस के रूप में निकाला...

जैसे ही दिल्ली में ठंड की शुरुआत होती है, प्रदूषण का खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पता चलता है कि इस प्रदूषण के लिए पंजाब में खेतों में जलाए जाने वाली पराली जिम्मेदार है। लेकिन अब एचपीसीएल इस कोशिश में लगी है कि पंजाब के विभिन्न 25 जगहों पर बायो प्लांट स्थापित किए जाएं ताकि किसान अपनी पराली को बायोगैस प्लांट की कंपनी को बेच सकें और व्यर्थ में जलाए जाने वाली पराली से इनकम अर्जित की जा सके। साथ ही प्रदूषण से भी निजात मिल सके। इसके लिए एचपीसीएल के अधिकारी लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसानों का झुकाव बायोगैस की तरफ हो।

यह जैविक खाद क्षेत्र के किसानों को मुफ्त में दिया जा रहा है।

2018 में भारत सरकार ने सतत योजना शुरूआत की